

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 350*

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन

*350. श्री बालूभाऊ धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक इकाइयों द्वारा कोयले का कुल उत्पादन, मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र—वार ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू मांग को पूरा करने हेतु कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु बनाई गई योजनाएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कोयले की मांग एवं आपूर्ति में व्याप्त अंतर को पाटने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“कोयला उत्पादन” के संबंध में श्री बालूभाऊ धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 17.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की अखिल भारत मांग नीचे दी गई है:

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
अखिल भारत वास्तविक मांग (मि.ट.)	836.93	898.17	968.00

कोल इंडिया लिमिटेड के लिए कोयले की मांग का अनुमान अलग से नहीं किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन और आपूर्ति नीचे दी गई है:

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सीआईएल द्वारा उत्पादन (मि.ट.)	554.14	567.36	606.89#	136.96*
सीआईएल द्वारा आपूर्ति (मि.ट.)	543.32	580.29	608.14#	153.29*
# अनंतिम	*जून 2019 तक			

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जून, 2019 तक सीआईएल का सहायक कंपनी-वार राज्य-वार कच्चे कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

कंपनी	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (जून तक) (अनंतिम)
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	23.58	25.61	29.40	7.13
	झारखंड	16.93	17.96	20.77	4.42
	कुल	40.52	43.57	50.16	11.54
बीसीसीएल	पश्चिम बंगाल	2.14	1.38	1.19	0.14
	झारखंड	34.90	31.23	29.85	6.32
	कुल	37.04	32.61	31.04	6.46
सीसीएल	झारखंड	67.05	63.41	68.72	11.66
एनसीएल	उत्तर प्रदेश	16.06	18.31	20.28	5.47
	मध्य प्रदेश	68.04	74.71	81.23	20.75
	कुल	84.10	93.02	101.50	26.22

डब्ल्यूसीएल	मध्य प्रदेश	5.23	4.45	3.93	0.78
	महाराष्ट्र	40.41	41.77	49.25	11.13
	कुल	45.63	46.22	53.18	11.91
एसईसीएल	मध्य प्रदेश	11.93	12.11	12.60	2.73
	छत्तीसगढ़	128.08	132.60	144.75	31.61
	कुल	140.00	144.71	157.35	34.33
एमसीएल	ओडिशा	139.21	143.06	144.15	34.78
एनईसी	असम	0.60	0.78	0.78	0.07
कुल		554.14	567.37	606.89	136.96

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (जून, 2019 तक) के दौरान सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों से कोयले की राज्य-वार आपूर्ति नीचे दी गई है:

(मिलियन टन में)

राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	(जून तक) (अनंतिम)
पश्चिम बंगाल	50.57	46.43	48.61	12.53
बिहार	18.04	18.98	17.96	4.67
झारखंड	31.29	35.26	31.77	7.65
ओडिशा	75.60	68.79	69.18	16.16
असम	0.91	0.91	1.51	0.38
उत्तर प्रदेश	86.95	92.22	91.43	23.16
पंजाब	14.77	12.99	17.42	4.53
हरियाणा	11.86	15.21	16.91	4.41
दिल्ली	1.69	1.35	1.55	0.40
राजस्थान	10.08	10.77	14.10	3.65
गुजरात	13.35	18.05	19.24	4.98
छत्तीसगढ़	67.66	74.51	94.98	23.75
मध्य प्रदेश	41.46	53.35	61.22	15.61
महाराष्ट्र	48.41	55.18	68.28	17.40
तमिलनाडु	18.94	22.49	24.61	6.42
कर्नाटक	4.83	5.49	4.39	1.13
आंध्र प्रदेश	24.87	26.14	24.62	6.37
अन्य राज्य	22.05	22.18	0.35	0.08
कुल	543.32	580.29	608.14	153.29

(ख) : घरेलू मांग को पूरा करने हेतु देश में वर्ष 2022-23 तक कोयले का कुल उत्पादन बढ़ाकर 1 बिलियन टन के स्तर तक करने की योजना है।

(ग) : कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पूरी तरह पाटा नहीं जा सकता क्योंकि कोकिंग कोयले की घरेलू उपलब्धता अपर्याप्त है तथा आयातित कोयले पर डिजायन किए गए विद्युत संयंत्र अपने उत्पादन हेतु कोयले का आयात करना जारी रखेंगे। तथापि, घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं। अखिल भारतीय कच्चा कोयला उत्पादन 2013-14 के 565.77 मि.ट. से बढ़कर 2018-19 में 730.35 मि.ट. (अनंतिम) हो गया है। अखिल भारतीय कोयला उत्पादन में 2013-14 से 2018-19 तक 164.58 मि.ट. की पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि 2008-09 और 2013-14 के बीच कोयला उत्पादन में 73.01 मि.ट. की वृद्धि हुई थी।

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 2013-14 के 462.41 मि.ट. से 2018-19 में 606.89 मि.ट. तक कर लिया है। कोयला उत्पादन में वर्ष 2008-09 तथा 2013-14 के बीच 58.68 मि.ट. की वृद्धि की तुलना में 144.48 मि.ट. की पर्याप्त वृद्धि है।

आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध अधिनियम, 2015) के तहत अभी तक कुल 84 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार का ध्यान घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने पर है जिसमें भूमि अधिग्रहण में सहायता के लिए राज्य सरकार के साथ कार्रवाई करना और कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे के साथ समन्वित प्रयास करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सीआईएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां उच्च यांत्रिकीकरण के साथ अधिक क्षमता वाली मेगा खानें (क्षमता > 10 मि.ट./वर्ष) चालू कर रही हैं।
- सीआईएल अपनी कार्य दक्षता में सुधार करने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पहले ही शुरू कर चुकी है। इस प्रयोजनार्थ 240 टी रियर डंपर के साथ 42 घनमीटर शॉवेल जैसी उच्च क्षमता वाली हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) लाई गई है।
- प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल द्वारा ओपनकास्ट खानों में बड़े स्तर पर सरफेस माइनर को लगाया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान सीआईएल में ओपनकास्ट कोयला उत्पादन का लगभग

50% कोयला उत्पादन सरफेस माइनर के माध्यम से था और बाद के वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है।

- भूमिगत खानों में प्रारंभिक बल कोयला निकालने / लदान प्रणाली, कोयला ड्रिलिंग एवं समर्थन प्रणाली, कोयला निकासी प्रणाली आदि के मशीनीकरण पर है। जहां संभव है, बेल्ट कन्वेयर्स के साथ-साथ उच्च क्षमता के लोड हाऊल डम्प (एलएचडी), साईड डिस्चार्ज लोडर्स (एसडीएल) एवं यूनिवर्सल ड्रिल मशीन का भी प्रयोग किया गया है।
